Peer Reviewed Journal for M.Phil., Ph.D. & Appointment of Teacher in Universities & College

ISSN : 2454-4655 VOLUME - 9 No. : 5, June - 2023

International Journal of Social Science & Management Studies

Peer Reviewed & Refereed Journal

Indexing & Impact Factor 5.2

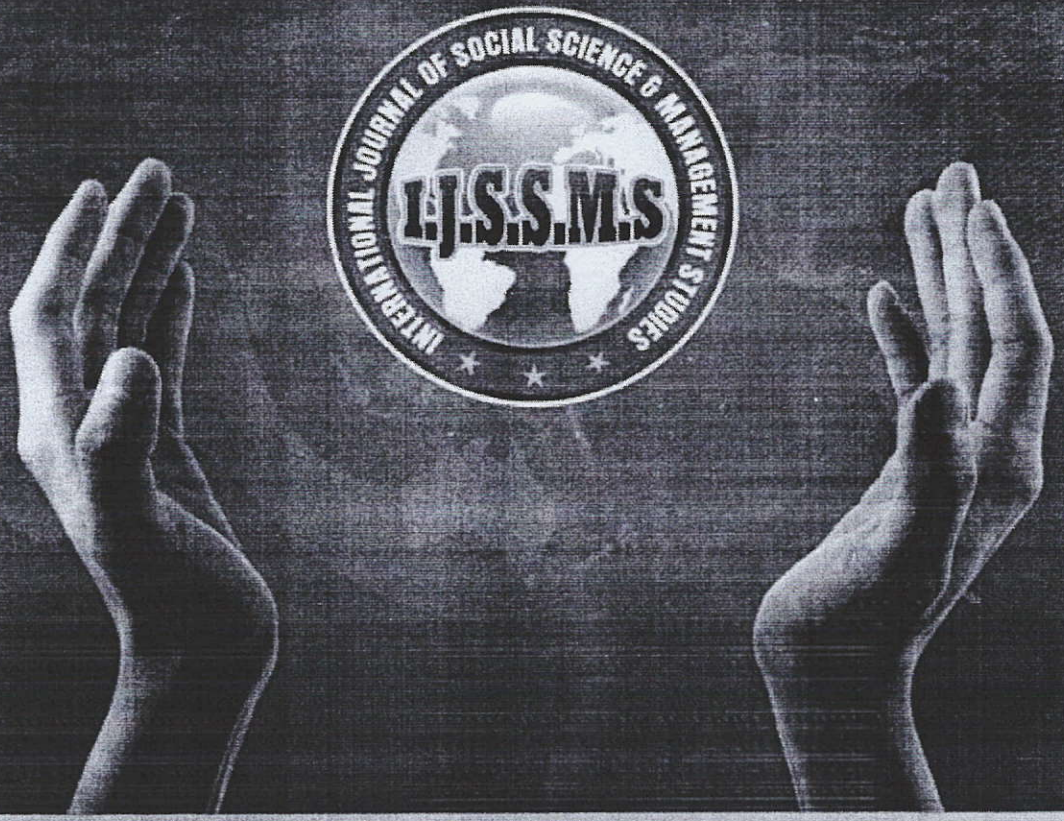

Indian Tech

GLOBAL CERTIFICATION SERVICES

International Scientific Research Solution

International Journal of Social Science & Management Studies

CONTENTS

S. No.	Paper Title	Author Name	Page No.
1	**गर्भावस्था के लिए स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाने वाली महिलाओं के बीच एक अध्ययन**	अनामिका वर्मा निधि सिन्हा	1-7
2	अज्ञेय के काव्य में श्रृंगार-वर्णन का स्वरूप	रोशनी, डॉ. मधुबाला गुप्ता	8-14
3	सामाजिक बदलाव राजनीतिक विकास का आधार	डॉ. हरिओम शर्मा	15-17
4	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भारतीय ग्रामीण कृषकों पर प्रभाव (गाजीपुर जनपद के सैदपुर विकासखंड पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)	नीलम चौहान डॉ. आशुतोष कुमार त्रिपाठी	18-21
5	डॉ. निरञ्जन मिश्र की कृतियों में काव्यशास्त्रीय महत्व	ललिता	22-24
6	उत्तर-औपनिवे शक समाज और निर्मल वर्मा का कथा साहित्य	मनोज कुमार संह	25-27
7	बुन्देलखण्ड की बालिकाओं का लोक पर्व सुआटा	डॉ. सुनीता	28-29
8	महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार	भारती पटेल प्रो. अशोक अहिरवार	30-35
9	व्यक्तित्व और कृतित्व : जयशंकर प्रसाद	अमित	36-37
10	राष्ट्रवाद का भारतीय चिंतन : एक पुनरावलोकन	Dr. Sanjali Gupta	38-41
11	**अर्थव्यवस्था का नवीकरण : आत्मनिर्भर भारत**	डॉ. तृप्ति भूषण	42-44
12	प्राथमिकता क्षेत्र उधार : भारत की बुनियादी जरूरतों के विकास के भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका	डॉ. उमेश शर्मा	45-50
13	शासकीय शालाओं में अध्ययनरत किशोरों के सामाजिक व्यवहार पर अभिभावकीय प्रोत्साहन के प्रभाव का अध्ययन	डॉ. रीना मेश्राम	51-52
14	ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं का राजनीतिक विश्लेषण	डॉ. अखिलेश कुमार शर्मा अनिक कुमार भटकर	53-54
15	मध्यप्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियमि 2005 के प्रभाव का व्यवहारिक अध्ययन	डॉ. अखिलेश कुमार शर्मा सोनम वाल्मीकि	55-58
16	ग्रामीण विकास में पंचायती राज का विकास और भूमिका	डॉ. भावना भदौरिया सुजाता अहिरवार	59-61
17	ग्रामीण महिलाओं का पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राजनीति में वर्चस्व एक अध्ययन	डॉ. धनंजय कुमार वर्मा लक्ष्मी बनवारी	62-64

International Journal of Social Science & Management Studies (I.J.S.S.M.S.)
Peer Reviewed–Refereed Research Journal, Indexing & Impact Factor - 5.2, Ex - UGC S.N. 5351
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 9, No. – 5, June - 2023
2023

ग्रामीण विकास में पंचायती राज का विकास और भूमिका

डॉ. भावना भदौरिया
शोध निर्देशक, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (मध्यप्रदेश)
सुजाता अहिरवार
शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्यप्रदेश)

सारांश :– जिस प्रकार से क्षेत्रीय पंचायतें भारत के ग्रामीण विकास परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरी है। ये स्थानीय सरकारी निकाय जो जिला, उप–जिला स्तर पर काम करती है। विकास योजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी जैसे कई कार्यों के लिए जिम्मेदार है प्रस्तुत पेपर ''ग्रामीण विकास में पंचायती राज का विकास और भूमिका'' भारत में क्षेत्रीय पंचायतों की स्थापना और कामकाज के पीछे राजनीतिक गतिशीलता की जॉच करता है।

ग्रामीण विकास भारतीय समाज का प्रमुख मुद्रा है। जो समय पर नीति–निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् , विभिन्न पंच वर्षीय योजनाओं के माध्यम भारत में ग्रामीण विकास के प्रयास किये जाते रहे हैं, परंतु व्यवहारिक धरातल पर अधिकांश भारतीय गांव सम्पूर्ण विकास से बहुत दूर है।

शोध पत्र भारतीय ग्रामीण समाज का सैद्धांतिक अध्ययन है तथा ग्रामीण विकास में पंचायती राज के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि पंचायती राज व्यवस्था ने भारत में ग्रामीण विकास को अप्रत्याशित गति प्रदान की है।

मुख्य शब्द :– ग्रामीण विकास में पंचायती राज का विकास और भूमिका।

प्रस्तावना :– भारत दुनिया का पहला सबसे अधिक आबादी वाला देश, अपने विशाल और विविध ग्रामीण परिदृश्य की विशेषता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली इसकी दो–तिहाई से अधिक आबादी के साथ ग्रामीण विकास देश में नीति निर्माताओं और विकास चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख संस्थागत ढ़ाचों में से एक पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) की प्रणाली है। जिसे 1992 में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से स्थापित किया गया था। ये संस्थाएं विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लागू करने और विकास में जमीनी स्तर की भागीदारी सुनिश्चित करने के जिम्मेदार है।

महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना पंचायती राज के माध्यम से साकार होती प्रतीत हो रही है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही उनकी इस परिकल्पना पर पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास हेतु बजट निर्धारित किया गया और हर संभव कोशिश की गयी की ग्राम–स्वराज्य अस्तित्व में आये।

ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता ही ग्राम–स्वराज्य के सपने को पूरा कर सकती है। गॉवों में भारत की आत्मा निवास करती है और जब तक भारत में ग्रामीण विकास की तेज लहर न हो तब तक भारत विकास की दृष्टि से पिछड़ा ही सिद्ध होगा। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के समन्वय से पंचवर्षीय योजनाओं का सफल संचालन होता आ रहा है तथा भारत में ग्रामीण विकास निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है।

पंचायती राज का वर्तमान परिदृश्य उत्साहवर्धक है क्योंकि अब सभी जातियों के सदस्यों को पंचायतीराज की सफलता के लिए एक साथ कार्य निश्चित रूप से ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन, ग्रामीण विकास करने और प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में सहायक है।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम–स्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के किए जाने की अपेक्षा करता है।

1. ग्रामीण स्तर पर जन विकास कार्य
2. ग्राम स्तर पर जन कल्याण
3. ब्लॉक स्तरीय पंचायती व्यवस्था

ब्लॉक पंचायती व्यवस्था तहसील स्तर पर होती है। जिसका उद्येश्य तहसील स्तर पर ग्राम विकास के कार्य समिति ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है।

जिला स्तरीय पंचायत व्यवस्था ग्रामीण आबादी को आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने किसानों को उन्नत बीजों की आपूर्ति करने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, पुस्तकालय, छात्रावास और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने लघु उधोग शुरू करने सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का आदि कार्य करती है।

ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय पंचायतों का विकास :– प्रस्तुत शोध पत्र भारत में क्षेत्रीय पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास के कई बुनियादी सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। इन कुछ सिद्धांतों में शामिल है : विकेन्द्रीकृत निर्णय – निर्माण – क्षेत्रीय पंचायतों के निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर देता है , विशेष रूप से ग्रामीण विकास योजनाओं की योजनां और कार्यन्वयन में। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विकास की पहल स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

भागीदारी योजना – ग्रामीण विकास में भागीदारी योजना के महत्व पर प्रकाश डालता है। क्षेत्रीय पंचायतों को नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय सामुदायों को शामिल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास पहल उनको जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी है।

समावेशी विकास – समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय पंचायतों की आवश्यकता पर जोर देता है, विशेष रूप से महिलाओं, दलितों और आदिवासी समुदायों जैसे हाशिर के समूहों के लिए, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार और असमानता के मुद्यों को संबोधित करने की आवश्यकता शामिल है।

सतत विकास – शोध पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय पंचायतों की आवश्यकता पर जोर देता है। इसमें टिकाऊ कृषि पद्धतियों को और लचीला समुदायों का निर्माण करने की आवश्यकता शामिल हो।

क्षमता निर्माण – क्षेत्रीय पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसमें शासन योजना और वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण शामिल है।

ग्रामीण विकास में मध्यप्रदेश सरकार की कुछ योजनाएँ :–

1. **मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना** – यह योजना किसानों की आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादकता बढाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
2. **मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना** – इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षाण प्रदान करना है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
3. **मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना** – इस योजना का उद्देश्य सड़कों और पुलों का निर्माण और उन्नयन करके ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क में सुधार करना है।
4. **मुख्यमंत्री ग्रामीण जल योजना** – इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
5. **मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना** – यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
6. **मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना** – इस योजना का उद्देश्य स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना है।
7. **मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना** – इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे रोजगार योग्य बन सके और एक स्थायी आजीविका अर्जित कर सकें।
8. **मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर आजीविका सहायता योजना** – इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका में सुधार करने और उधमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन प्रस्तुत करना।
2. भारतीय ग्रामों का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना।
3. ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन की समीक्षा करना।
4. स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में ग्रामीण विकास की समीक्षा करना।
5. भारतीय ग्रामीण समाज की गति एवं दिशा की समीक्षा करना।
6. ग्रामीण विकास के मार्ग में आने वाली समस्याओं को ज्ञात करना।
7. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज के मध्य संबंध ज्ञात करना।
8. पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या करना।
9. ग्रामीण विकास हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना।
10. भारत के ग्रामीण विकास में पंचायतीराज व्यवस्था के योगदान से अवगत कराना।

शोध पद्धति – प्रस्तुत अध्ययन व्याख्यात्मक एवं समीक्षात्मक शोध की श्रेणी में आता है। अध्ययन पूर्णतः मौलिक एवं वैज्ञानिकता पूर्ण है। अध्ययनकर्ता ने इसके कार्य करने में वास्तुनिष्ठता का पूर्ण ध्यान रखा है। विभिन्न प्रकाशित शोध पत्र अध्ययन का आधार रहे हैं

क्योंकि उनमें प्रकाशित एवं उपलब्ध द्वितीयक तथ्य इस अध्ययन में प्रयोग किये गये हैं और उनके आधार पर ही निष्कर्ष निकाले गये हैं।

निष्कर्ष :– अंत में ग्रामीण विकास में यह अध्ययन ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न पहलों और योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण भी प्रदान करता है। ये योजनाएँ स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा ग्रामीण बुनियादी ढ़ांचे में सुधार और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने पर सरकार के ध्यान को दर्शाती है। अंततः अध्ययन ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय पंचायतों के महत्व को रेखांकित करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकस पहलो में निरंतर निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह अध्ययन मध्यप्रदेश और अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में रूचि रखने वाले नीति निर्माताओं शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

1. भारत एक ग्राम प्रधान देश तथा ग्रामीण विकास भारत में सार्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्धा है जिसकी ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार निरंतर ध्यान दे रही है और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।
2. ग्रामीण विकास के बिना भारत जैसे विशाल एवं प्रजातान्त्रिक देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते।
3. पंचायतीराज महात्मा गॉधी की ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना का एक साकार रूप है जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ग्रामपंचायतों के माध्यम से शासन संचालित किया जाता है।
4. 73 वां संशोधन जो 1992 में किया गया था इस दिशा में सराहनीय कदम था।
5. पंचायतीराज व्यवस्था राज को चलाने में पंचायतीराज संस्थाओं का विशेष योगदान है जो सफल संचालन में अपना विशेष योगदान देती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

- मध्यप्रदेश सरकार (2021) मुख्यमंत्री ग्रामीण जल योजना।
- मध्यप्रदेश सरकार (2021) मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना।
- मध्यप्रदेश सरकार (2021) मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना।
- मध्यप्रदेश सरकार (2021) मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर आजीविका सहायता योजना
- मध्यप्रदेश सरकार (2021) मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना।
- मध्यप्रदेश सरकार (2021) "भारत में पंचायती राज" पंचायती राज मंत्रालय।
- जेना, पीके (2016) भारत में विकेंद्रीकृत शासन और ग्रामीण विकास पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषण। आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 21(7), 37–41
- जोशी, ए. (2016) भारत में विकेंद्रीकृत शासन और ग्रामीण विकास। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च, 6(4), 2101–2105
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (2021) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा)।
- योजना आयोग, भारत सरकार (2014) गरीबी के आकलन के लिए पद्धति की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट।
- गिल एम.एस. एवं रमा – Panchayati raj institutions and rural development in Punjab, एशियाई जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज एंड हुमानिटीज 2(11), 2012
- हेनरी मैडिक – Can Panchayati raj Becomes the Agency for Integrated Rural Development, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जुलाई 1978
- के ईस्वरा रेड्डी – Rol of Panchayati raj institutions in Rural in Rural Development & with Special Reference to Anantapuramu District of Andhara Pradesh, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हुमानिटीज एंड सोशल साइंस स्टडीज, 2014
- महिपाल – Panchayati raj and Rural Governance: Experiences of a decade, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 39 (2), 2004
- सुमन कुमारी, शहबाज आलम – Rule of Gram Panchayat in Rural Development: I Study Of Mathura District [Uttar Pradesh] इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च 5 (3), फरवरी 2016।